www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE — सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 117 | जौनपुर गुरूवार, 11 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

फ्लाइट कैंसिलेशन पर काबू पाने के लिए इंडिगो को बड़ा झटका

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया। जानकारी के अनुसार इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा मौजूद थे। इंडिगो अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति और पायलट और क्रू रॉस्टर की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की गई।उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयरलाइन के सीईओ के साथ बैठक के बाद कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया। बैठक के बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ्लाइट टाइम–टेबल और अपर्याप्त संचार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण कई यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रहने के साथ ही इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्टेबलाइजेशन (स्थिरीकरण) उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है।

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एसआईआर को ठहराया गलत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गलत ठहराया है। उन्होंने सवाल उठाए कि जिस तरह एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उससे मतदाता सूची में 50 प्रतिशत लोगों के वोट ही बच सकेंगे। रामगोपाल यादव ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, ष्चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर खुद ही भ्रमित है। बड़े पैमाने पर बीएलओ ने लोगों को अनुपस्थित, स्थायी रूप से विस्थापित और मरा हुआ दिखाया, लेकिन हो सकता है कि उसमें से भी कुछ जिंदा निकल आएं। फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए सपा सांसद ने कहा, षफिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र में 3,82,160 मतदाता हैं। मंगलवार तक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिखाया गया है कि 3,82,159 फॉर्म बांटे गए। इनमें से 10,703 मतदाताओं को मृत, 11,964 को अनुस्थित और 29,364 को स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट दिखाया गया। सवाल यह है कि जब इतने सारे लोग मृत, अनुस्थित और शिफ्ट हो चुके हैं, तब 100 प्रतिशत फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ?ष रामगोपाल यादव ने आगे कहा, ष्इसमें सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि 2003 का वोटर जो 2025 में भी वोटर है, उसे चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

घबराइए मत, हर समस्या का होगा प्रभावी समाधान, सुनीं 200 लोगों की समस्याएं : आदित्यनाथ योगी

गोरखपुर, (संवाददाता)। मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, 'घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा।' जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। आत्मीयता के पुट में 'कहां से आए हैं, क्या बात है', कहते हुए एक–एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी परेशान होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। एक महिला ने मकान जला दिए जाने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे।

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर सत्ता पक्ष–विपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बुधवार शाम 5 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बहस का समापन करते हुए चुनाव सुधारों पर बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे के आसपास लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोलेंगे। इससे पहले रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ ठोस सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने हम सभी को निराश किया है। संसद का समय अमूल्य है, और देश विपक्ष के नेता से बेहतर भाषण की उम्मीद करता है। संसद में चुनाव सुधार

पर हो रही बहस के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को एनआरसी का नाम देकर मतदाता अधिकारों पर हमला बताया, तो भाजपा ने कांग्रेस पर वोट चोरी के पुराने आरोप लगाए ।लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में तीन प्रमुख सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा राष्ट्र–विरोधी कृत्य वोट चोरी हैय जब आप वोट नष्ट करते हैं, तो भारत की अवधारणा नष्ट करते हैं।ष राहुल ने मांग की कि चुनाव से कम से कम एक महीने पहले मशीन–रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले।

राज्यसभा में उठा हवाई यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने का मुद्दा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए ए रहीम ने बुधवार को राज्यसभा में हवाई यात्रियों की दिक्कतों और उनसे मनमाना किराया वसूलने का मुद्दा उठाया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। रहीम ने सदन में सभापति की अनुमति से उठाये जाने वाले मामलों के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके लिए अकेले इंडिगो एयरलाइन जिम्मेदार नहीं है बल्कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नीतियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस लोगों की दिक्कतों का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रही हैं। सरकार का एयरलाइंस पर कोई नियंत्रण नहीं है । उन्होंने कहा कि आज उन्होंने स्वयं तिरूवनंतपुरम के लिए टिकट बुक करने की कोशिश की तो इसमें किराया 66 हजार रूपये दिखाया गया है जिसे किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सरकार से इसके समाधान की दिशा में कदम उठाने की मांग की। भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े ने महाराष्ट्र के नांदेड में मानव निर्मित बाढ आपदा के कारण किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में स्थित श्रीरामसागर परियोजना से आने वाले बैक वाटर के पानी से इन गांवों की आबादी तथा खेती की जमीन डूब जाती है। उन्होंने मांग की कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और इन किसानों को सहायता राशि दी जानी चाहिए। भाजपा के दोरजी त्शेरिंग लेप्चा ने नाथू ला के जरिये चीन के साथ व्यापार के मार्ग को जल्द शुरू किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ इस बारे में भारत की सहमति बन गयी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी और उनकी वित्तीय हालत सुधरेगी। भाजपा के हर्ष वर्धन श्रृंगला ने दार्जीलिंग चाय बागानों से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का मुद्दा उठाया ।

सीएम रेखा गुप्ता ने भलस्वा ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज भलस्वा क्षेत्र में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। वर्ष 2016 में तैयार लेकिन वर्षो से खाली पड़े इन फ्लैट्स को देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और इसे दिल्ली के गरीब परिवारों के साथ सबसे बड़ा अन्याय बताया। मुख्यमंत्री ने लाखों झुग्गीवासी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पिछली सरकारों पर तीखा हमला किया और कहा कि हमारी सरकार लगातार झुग्गीवासियों को उनके हक का पक्का घर और हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आज इन फ्लैट्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन फ्लैट्स को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि इन्हें झुग्गीवासियो को आवंटित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने वहां एक मॉडल रिहायशी परिसर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ इस निरीक्षण दौरे में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष सूद एवं विधायक श्री दीपक चौधरी सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उन लाखों गरीब परिवारों के बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जो आज भी झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने भलस्वा परिसर में बने 7,400 फ्लैट्स के बारे में उल्लेख करते हुए बताया कि ये फ्लैट वर्ष 2016 में बनकर तैयार हुए थे और अब इनकी हालत खंडहर जैसी हो गई। पिछली सरकार ने इन मकानों को किसी भी गरीब परिवार को आवंटित नहीं किया। यह दिल्ली की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि उस समय ये फ्लैट गरीबों को आवंटित कर दिए गए होते, तो आज वे परिवार अपने घरों में सुख और सम्मान के साथ रह रहे होते। वर्षों तक खाली पड़े रहने के कारण ये मकान जर्जर हो गए और इनमें रखा सामान गायब हो गया है । मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक नया, आधुनिक और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित मॉडल तैयार किया है।

सोनिया गांधी को कोर्ट की झटका

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के लिए उनका 79वां जन्मदिन कानूनी उलझनों के साथ आया है। जिस दिन वह अपना जन्मदिन मना रही थीं, उसी दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक पुराने मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के साथ–साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 के लिए तय की है। दरअसल, यह पूरा मामला एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका से जुड़ा है जिसे विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर किया है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत (मजिस्ट्रेट कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने याचिकाकर्ता के वकील पवन नारंग की शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी, लेकिन उनका नाम इससे तीन साल पहले यानी 1980 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। याचिकाकर्ता के दावों के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। वरिष्ठ वकील पवन नारंग ने कोर्ट में दलील दी कि जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक ही नहीं थीं, तो उनका नाम मतदाता सूची में कैसे आया? इसका सीधा मतलब है कि इसके लिए कुछ दस्तावेज जाली, मनगढ़ंत और झूठे तरीके से तैयार किए गए होंगे। वकील ने कोर्ट से कहा कि वे अभी चार्जशीट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं कि पुलिस कम से कम इस पहलू की जांच करे कि आखिर बिना नागरिकता के नाम लिस्ट में कैसे चढ़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस तथ्यों पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट आना पड़ा।

शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने मुलाकात की। इनमें इंटेल के सीईओ लिप–बू टैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस और उसकी भारतीय इकाई के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद लिप–बू टैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश् पर पोस्ट में कहा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हमने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग और भारत के लिए अपार संभावनाओं वाले विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं और इंटेल भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ पीएम मोदी ने कॉग्निजेंट

के सीईओ रवि कुमार एस और उसकी भारतीय इकाई के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर से मुलाकात की। इस पर कॉग्निजेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश् पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे सीईओ रवि कुमार एस और कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जहां उन्होंने एआई को अपनाने में तेजी लाने और एआई क्षमताओं एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास को आगे बढ़ाने पर एक प्रेरक बातचीत की।

मोदी जी आधा समय विदेश में बिताते हैं : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लगभग आधा समय देश के बाहर बिताते हैं।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। इस दौरान वह भारतीय समुदाय से मिलेंगे और जर्मन मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा ने राहुल गांधी की आगामी विदेश यात्रा पर तंज कसा और कहा कि श्राहुल तो विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि पर्यटन के नेता हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि संसद 19 दिसंबर तक चल रही है। लेकिन राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल विदेश में थे और बाद में जंगल सफारी पर चले गए थे। प्रियंका गांधी ने भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा, मोदी जी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं... फिर विपक्ष के नेता के विदेश जाने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बताया कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे और उनके साथ सैम पित्रोदा भी होंगे।

कांग्रेस लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देगी : वेणुगोपाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि सत्तारूढ़ दल संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है लेकिन उनकी पार्टी श्वोट चोरीश के विरुद्ध लड़ती रहेगी और जनता के सहयोग से लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देगी। वेणुगोपाल ने चुनाव सुधारों पर मंगलवार को अधूरी रह गयी चर्चा की बुधवार को शुरुआत करते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए तरह–तरह के तरीके निकाले जा रहे हैं, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर आंच नहीं आने दी जायेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता उठ खड़ी होगी और क्रांति लायेगी। उन्होंने कहा कि आज निष्पक्ष चुनाव का विचार बदल दिया गया है। चुनाव के समय प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग सक्रिय हो जाते हैं और विपक्षी दलों के नेताओं और उनके दलों को निशाना बनाया जाता है। पिछले लोकसभा चुनावों के ऐन पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिये जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर विवरणी दाखिल करने में मात्र कुछ दिनों की देरी के लिए कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के खाते फ्रीज कर दिये गये। यह सारे क्रियाकलाप लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है।वेणुगोपाल ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने देने संबंधी कानून क्यों लाया गया चुनाव आयुक्तों को इतनी सुरक्षा दिये जाने के पीछे क्या मंशा है? यह संदेह उत्पन्न करता है। आज जनता के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर शंकायें उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जितनी याचिकायें हाल के दिनों में न्यायालयों में दाखिल की गयी हैं, उतने मामले पहले कभी नहीं देखे गये।उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयुक्त मिलकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। सत्तारूढ़ दल चुनाव आयोग को यह अपराध क्यों करने दे रहा है। सत्तारूढ़ दल लोक तंत्र की हत्या कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर करते हैं, वह जानना चाहते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित समिति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया?कांग्रेस नेता ने कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों पूरी करायी जा रही है। पहले भी मतदाता सूची में संशोधन और सुधार हुए हैं, जिसके लिए संबंधित कर्मियों को छह–छह महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब मात्र दो महीने में एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी दबाव के कारण बड़ी संख्या में बीएलओ ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने मशीन से पढ़ी जाने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने, मतदान की सीसीटीवी वीडियो 45 दिनों में ही नष्ट न करने और एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिये जाने की मांग की।

संपादकीय

किराएदार के अधिकारों का संरक्षण

यह सोच अपने–आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो। भारत सरकार का कहना है कि मकान किराया संबंधी नए नियमों में उसने मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। चूंकि अब मकान किराए पर देने से संबंधित दस्तावेज का 60 दिन के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसलिए समझा जा सकता है कि नए नियमों का मकसद टैक्स वसूली को सुनिश्चित करना भी है। बहरहाल, यह सोच अपने–आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो। तो प्रावधान किया गया है कि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, सुरक्षा जमा (डिपॉजिट) की सीमा तय कर दी गई है और किराया वृद्धि को भी नियमित किया गया है। आवासीय मकसद के लिए किराए पर लगाए गए मकान के मालिक अब दो महीने से अधिक का डिपॉजिट नहीं ले सकेंगे। खासकर बड़े शहरों में चलन छह महीने या सालभर का एडवांस किराया लेने का रहा है। साथ ही मकान मालिक अब अचानक किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए उन्हें पहले से नोटिस देना होगा। इसी तरह मकान मालिक अब किसी किरायेदार को अचानक घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निश्चित नोटिस पीरियड और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। किराएदार किसी मरम्मत के लिए शिकायत करता है, तो मकान मालिक को ऐसा 30 दिन के अंदर कराना होगा। वरना, किराएदार को अधिकार होगा कि वह खुद मरम्मत करवा कर आए खर्च को किराए में एडजस्ट कर ले। उधर चूंकि किराएदारी के हर समझौते का डिजिटल स्टांप करवा कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तो उससे मकान मालिकों को सुरक्षा मिलेगी। यह भी तय किया गया है कि संबंधित ट्रिब्यूनल को सभी विवादों का निपटारा 60 दिन के अंदर करना होगा। ये अच्छी पहल है। मगर, यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं उलझाऊ ना हों तथा इसे कराने की सारी जहमत किराएदारों को ही ना उठानी पड़े।

मैकाले की विरासत का अभिनंदन

हरिशंकर व्यास

मैकाले को बेचारा माने या महान? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोसा है। कहा है कि मैकाले भारतीयों की श्गुलामी की मानसिकताय का जिम्मेदार है। पर फिर अगले दिन उन्होंने मैकाले की विरासत का अभिनंदन किया। मत्था टेका। पेचीदा मसला है। सोचें, भारत की आज बनावट और बुनावट क्या है? नरेंद्र मोदी यदि बतौर प्रधानमंत्री सत्ता भोग रहे हैं, तो किसके कारण? इसके लिए वे संविधान को पूजते हैं। और इस संविधान की बनावट–बुनावट क्या है? मोटामोटी अंग्रेज मैकाले का सपना। मैकाले, बर्क, जेम्स मिल, लॉर्ड कजर्न यानी मालिक अंग्रेजों के कानूनों, इस्पाती खांचे–ढांचे की शासन–पद्धति का एक कलमबद्ध ग्रंथ! पर क्या इस सत्य का भान हम भारतीयों को है? लगभग नहीं। यही मैकाले–अंग्रेजों की महान उपलब्धि है। वे एक ऐसी कधैम, एक ऐसा देश रच गए जिन्हें इतना भी अहसास नहीं कि स्वतंत्र भारत की बनावट का आधार ही गुलामी की अंग्रेज व्यवस्था है।

यही मैकाले, लॉर्ड कजर्न या ब्रिटिश संसद से ठप्पा लगे हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू करवाने वाले गवर्नर–जनरल लॉर्ड विलिंग्डन की महानता का प्रमाण है। ये भारतीयों को इतना अज्ञान में डुबो गए कि उन्हीं की विरासत वाला शासन और उसका संविधान आज भी यथावत है पर उसे प्रधानमंत्री मोदी पूजते हैं और अपने को विश्वगुरु भी कहते हैं! मैकाले की शिक्षा नीति से निश्चित ही एक सीमा तक (आखिर उससे पहले भी सदियों से गुलाम थे) भारतीयों में गुलामी की मानसिकता बनी। पर उसका आजादी के बाद और पुख्ता होना तो स्वतंत्र भारत के शासन–सत्ता तंत्र से ही है। इस तंत्र के राजाधिराज पिछले ग्यारह वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हैं। और वे संविधान की महिमा का बखान करते हुए नागरिकों से क्या आह्वान करते हैं? यह कि संविधान में बताए कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निभाना चाहिए। और क्या हैं ये कर्तव्य? मतलबकृसरकार को माईबाप मानो। सत्ता की शान में कोई गुस्ताखी नहीं।

पता है, नागरिकों को कर्तव्यों में बाँधने और सरकार को मनमानी करने की सुविधा देने वाला संविधान प्रावधान कब बना था? जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया हुआ था। कर्तव्य की बात 1950 के मूल संविधान में नहीं थी। इन्हें सोवियत संविधान से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय मौलिक कर्तव्य के नाम से 42वें संशोधन (1976) में संविधान में डलवाया था। पर इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का फर्क है। उन्होंने या उनके आगे–पीछे के किसी प्रधानमंत्री ने सत्तावान बनने के बाद संविधान की वह पूजा–अर्चना नहीं की, जैसी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार करते हैं। जबकि हिसाब से संघ परिवार और भारतीय संस्कृति के विचारकों ने संविधान को लेकर संविधान सभा की बहस में यह कहा हुआ है कि यह मानो अंग्रेज शासन की रचना है। संविधान सभा में डॉ. रघुवीर से लेकर के.एम. मुंशी, के.टी. शाह, एच.वी. कामथ, संपूर्णानंद, रविशंकर शुक्ला आदि कई कांग्रेसी, वामपंथी, राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान के भारतीयकरण यानी देशज बनाने के ढेरों तर्क दिए और भाषण किए। डॉ. रघुवीर ने भारत की सभ्यतागत राष्ट्र (हिंदू राष्ट्र नहीं) की रचना के लिए सांस्कृतिक तत्वोंकृत्रृत, सत्य, धर्म–जन्य कर्तव्य, राष्ट्रीय भाषाकृजैसे सूत्रों को संविधान में समाहित करने की आवश्यकता बताई। उनका आग्रह था कि भारत का संविधान केवल कधनून का दस्तावेज न हो बल्कि यह भारतीय सभ्यता का भाव–दस्तावेज भी हो। पर उन्हें नहीं सुना गया। तभी उन्होंने अंत में कहाकृयह संविधान भारतीय नहीं लगताय यह भारत की धरती में उगा हुआ वटवृक्ष नहीं, बल्कि विदेशी पौधा है। डॉ. रघुवीर से भी अधिक मुखर के. एम. मुंशी, एच.वी. कामथ, के.टी. शाह थे। के.टी. शाह विचारों में वामपंथी थे, लेकिन उनका भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के आग्रह के साथ तर्क था कि संविधान में यह चिन्हित होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत क्या है। इसी तरह नंदलाल बसु, रविशंकर शुक्ला, संपूर्णानंद, लक्ष्मीकांत माने, अनंतराय चौधरी आदि ने देशज शिक्षा, भाषा, नैतिक मूल्यों के सूत्र संविधान में डालने की माँग की। लेकिन मैकाले का स्टील फ्रेमवर्क, आई.सी.एस. नौकरशाही, प्रभुवर्ग और पंडित नेहरू ने किसी की नहीं सुनी। मानने वाले मानते हैं कि डॉ. आंबेडकर ने संविधान लिखा। असलियत में अंग्रेज संविधान का खाका बना गए थे। सो मैकाले की संतानों ने जैसा चाहा वैसा ही औपनिवेशिक ढांचे को लगभग अपनाते हुए संविधान रचा। उसे लिखना भी क्या थाकृगवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सरचनात्मक निरंतरता पर ठप्पा था। इस वास्तविकता का डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में मजाक–आलोचना के अंदाज में भी आभास कराया। उन्होंने कहा था कि संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तीन–चौथाई हिस्से उठा लिए गए हैंकृतो आयरिश संविधान से भी हिस्से लिए गए! ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि नेहरू और उनकी ओर से संविधान मसौदा प्रारूप बनाने वाले आई.सी.एस. अफसर बी.एन. राउकृमैकाले की शिक्षा से पोषित स्टील–फ्घ्रेम की अफसर जमातकृपूरी तरह लॉर्ड कजर्न के फलसफे की मुरीद थी। और लॉर्ड कजर्न का क्या सूत्र था?

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

ललित

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर–जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही–सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर–लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़धी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं। गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है–क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर–जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं–सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग–ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं। नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं–"दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा", "उच्च स्तरीय जांच की जाएगी", "मुआवजा दिया जाएगा", लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव–मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर

ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैंय प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता हैय समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन–स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक–दमक पर। गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है। हमारे नीति–नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान–माल को ही क्षति नहीं पहुंचातीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं ।

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

नीरज

हिंदू–बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार–बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया हैय यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे 'दीपथूण' (पत्थर के दीप–स्तंभ) पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 'दीपथूण' पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों (अरुपडई वीड़कु) में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम हैय हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति भ्त्–ब्ध विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो। इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निधारिण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून–व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया। दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और ।प्डप्ड से संबद्ध 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है। देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, वह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और चिंताजनक मिसाल है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर–प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से भक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिक्री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित हिस्सों में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपथूण पर दीप जलाना मंदिर–परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है। फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद गहराता गया और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया। यह वही मानसिकता है जो डीएमके और उसके सहयोगियों की राजनीति में बार–बार दिखाई देती है, जहाँ बहुसंख्यक आस्था को दबाकर तुष्टिकरण को राजनीतिक लाभ का साधन बना दिया जाता है। यह संयोग नहीं है कि वही दल, जिसके नेताओं ने अनेक बार सनातन धर्म को नष्ट करने योग्य कहा, वही आज दीपथूण में दीप जलाने का विरोध कर रहा है। यहाँ प्रश्न केवल परंपरा का नहीं, बल्कि अधिकारों का है। जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद था कि भक्त दीपथूण पर दीप जला सकते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा उसे लागू न करना न केवल न्यायालय की अवमानना है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का खुला हनन भी है। जिस प्रकार अदालत ने पुलिस और प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि न्यायपालिका का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, वह बताता है कि सरकार किस हद तक अपनी सीमाएँ भूल चुकी है। लेकिन इससे भी खतरनाक कदम था 107 विपक्षी सांसदों द्वारा न्यायाधीश

डीजीसीए और इंडिगो की मनमानी का नतीजा

अजीत द्विवेदी

भारत में अब किसी भी घटनाक्रम की, चाहे वह एक बड़े संकट के रूप में क्यों न प्रकट हुआ है, तर्कसंगत या तथ्यात्मक व्याख्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश राजनीतिक रूप से इतना विभाजित इतिहास में कभी नहीं रहा है। पूरा देश मोदी समर्थन या मोदी विरोध में बंटा हुआ है। तभी हर घटनाक्रम की व्याख्या इसी बाइनरी में होती है। मोदी विरोधी हर घटनाक्रम को एक निर्धारित दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। उनकी सारी व्याख्या एक ऐसे आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पर आधारित होती है, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा रची गई है। इंडिगो संकट की व्याख्या भी उसी संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर हो रही है।

अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग बता रहे हैं कि 27 नवंबर को अडानी समूह ने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नीक सेंटर यानी एफएसटीसी का अधिग्रहण किया है। यह देश की सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग संस्था है। अडानी समूह ने 820 करोड़ रुपए में इस कंपनी में 72 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे को इंडिगो संकट से जोड़ा जा रहा है। यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि अब देश में जल्दी ही 20 हजार से ज्यादा पायलटों की जरुरत होने वाली है और उसकी आपूर्ति अडानी के मालिकाना वाले एफएसटीसी से होगी। सवाल है कि क्या 20 हजार पायलट की जरुरत होगी और अडानी ने पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किया है इसलिए इंडिगो का इतना बड़ा संकट खड़ा कराया गया है ताकि पायलट की कमी पर फोकस बने और अडानी को पचास, सौ करोड़ रुपए की कमाई हो जाए? यह बहुत बेकार का तर्क है। इंडिगो संकट की वैचारिक खांचे से व्याख्या करने वाले इस समूह का दूसरा निष्कर्ष यह है कि इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब ने 36 करोड़ रुपए के और उसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिनमें से ज्यादातर बॉन्ड भाजपा को दिए गए। तो क्या इस रुपए के बदले में भाजपा की केंद्र सरकार ने इंडिगो को इतना बड़ा संकट खड़ा करने की इजाजत दी? यह निष्कर्ष पूरी तरह से गलत नहीं है तब भी अधूरा है। हो सकता है कि चंदे के लिहाज में सख्त कार्रवाई नहीं हुई हो लेकिन संकट इस वजह से खड़ा नहीं हुआ। असल में इंडिगो का संकट नागरिक विमानन मंत्रालय व नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और व्यापक रूप से केंद्र सरकार के निकम्मेपन और एकाधिकारवादी निजी कंपनी इंडिगो की मनमानी का नतीजा है। अगर मौजूदा संकट की बात करें तो सरकार का निकम्मापन यह है कि उसने मार्च 2024 में एक नियम बनाया और उसे लागू करने के लिए एक जुलाई 2025 और एक दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की और इतना समय देने के बाद भी इसे ठीक तरीके से लागू नहीं करा पाई। सवाल है कि क्या डीजीसीए को पता नहीं है कि देश के विमानन सेक्टर में करीब 65 फीसदी का हिस्सा रखने वाली और हर दिन 23 सौ उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो के पास पर्याप्त संख्या में पायलट नहीं हैं? निश्चित रूप से डीजीसीए को इसकी पूरी जानकारी थी क्योंकि उसके पास इस बात का पूरा आंकड़ा है कि देश में पायलट ट्रेनिंग के कितने इंस्टीट्यूट्स को मान्यता दी गई है, उनमें से प्रशिक्षित होकर कितने पायलट्स निकल रहे हैं और कितने लोगों को इंडिगो में नौकरी मिल रही है। उसे यह भी पता है इंडिगो के पास कितने जहाज हैं, कितनी उड़ानें हैं और कितने पायलट्स हैं। फिर भी उसने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी एफडीटीएल नियम लागू किया तो इसका रत्ती भर प्रयास नहीं किया कि सबसे बड़ी विमानन कंपनी इसे लागू करने की तैयारी शुरू करे। इसी साल अक्टूबर में डीजीसीए ने पर्याप्त पायलट ट्रेनिंग नहीं होने के लिए इंडिगो के ऊपर जुर्माना लगाया था। जाहिर है उसको पता है कि एफडीटीएल नियम को लागू करने के लिए इंडिगो ने कोई तैयारी नहीं की है। फिर भी उसने इंडिगो को तैयारी के लिए बाध्य नहीं किया और न समय रहते समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया। यही पर इंडिगो की मनमानी की बात आती है। डीजीसीए ने तमाम संबंधित पक्षों यानी विमानन कंपनियों से सलाह मशविरा करके एफडीटीएल नियम तैयार किया और लागू करने की तारीख तय की। बाकी कंपनियां, जिनके पास कम जहाज हैं उन्होंने पर्याप्त संख्या में पायलट नियुक्त किए। तभी एक दिसंबर को एफडीटीएल नियम लागू होने का असर उनकी सेवाओं पर नहीं पड़ा। आखिर एयर इंडिया की भी हर दिन एक हजार से ज्यादा उड़ानें होती हैं। लेकिन वहां पायलट और चालक दल की कमी से उड़ानें रद्द नहीं हुईं। जाहिर है इंडिगो ने सबसे बड़ी कंपनी होने और भारत के आकाश पर एकाधिकार होने के अहंकार में न तो पायलट भर्ती की और न चालक दल के अन्य सदस्यों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की। उसको विश्वास था कि वह बांह मरोड़ कर सरकार से मनमाफिक फैसला करा लेगी। उसने वही किया। उसने नए नियम लागू करने की बजाय उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी। उसने पांच दिसंबर को डेढ़ हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द की थीं, जिसके बाद सरकार पीछे हटी। उसको पता था कि यात्री परेशान होंगे तो सरकार पीछे हटेगी। सो, उसने लाखों यात्रियों को जान बूझकर परेशान किया और सरकार को झुकाया। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का इशारा है और सिर्फ एक सेक्टर का संकट नहीं है। जिस तरह समय के साथ विमानन सेक्टर में एक कंपनी का एकाधिकार बना है वैसे ही ऊर्जा से लेकर संचार और सीमेंट, हवाईअड्डा व बंदरगाहों से लेकर खाने पीने की चीजों तक चुनिंदा कंपनियों का एकाधिकार बना है। एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था बनाने में सीधे तौर पर सरकार का हाथ है तो उन एजेंसियों का भी हाथ है, जिनकी जिम्मेदारी इन बातों पर निगरानी करने की है। सोचें, भारत में एक प्रतिस्पर्धा आयोग भी है, लेकिन हर जगह प्रतिस्पर्धा समाप्त होती जा रही है या की जा रही है और यह आयोग कुछ नहीं करता है। इसके बरक्स अमेरिका के एंटी ट्रस्ट कानून और उसे लागू कराने वाली एजेंसी को देखें तो फर्क साफ नजर आएगा। वहां नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदा है तो एंटी ट्रस्ट कानून के तहत उसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन भारत में ऐसी कोई पहल नहीं होती है। अगर सिर्फ विमानन सेक्टर को देखें तो 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। उसके बाद 2018 में जेट एयरवेज दिवालिया हो गई और पांच साल बाद 2023 में गो एयर बंद हो गई। और इसी बीच भारत सरकार ने अपनी कंपनी औने पौने दाम में टाटा समूह को बेच दी। उससे पहले सहारा एयरलाइंस, डेक्कन और एमडीएलआर जैसी कई विमानन कंपनियां बंद हुई थीं। एक तरफ विमानन कंपनियां धड़ाधड़ बंद हो रही थीं और दूसरी ओर सरकार उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में हवाईअड्डे बनाने या बड़े हवाईअड्डों के निर्माण और कनेक्टिविटी की घोषणा करने में लगी थी। आखिर सरकार ने सोचा क्यों नहीं कि 10 साल बाद विमानन का परिदृश्य कैसा होगा? कितने विमानों, कितने पायलटों, चालक दल के सदस्यों, हवाईअड्डों आदि की जरुरत होगी? विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने इस बारे विचार ही नहीं किया। अगर विचार किया होता तो जेट एयरवेज को रिवाइव करने की कोशिशों को कामयाब बनाया जाता। गो एयर के विमान अलग अलग हवाईअड्डों पर खड़े हैं उनको चालू कराने की कोशिश की गई होती। आखिरी सरकार आइडिया और वोडाफोन के कर्ज को इक्विटी में बदल कर उसे बार बार राहत दे रही है। क्या वैसी राहत विमानन सेक्टर की कंपनियों को नहीं दी जा सकती है? यह सही है कि इंडिगो का एकाधिकार सरकार ने नहीं बनवाया है। उसने बेहतर प्रबंधन से एकाधिकार बनाया लेकिन किराए से लेकर सेवा की खराब गुणवत्ता तक में सरकार और डीजीसीए ने उसकी मनमानियों की अनदेखी की है, ।

लखनऊ में 65 एकड़ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार, पीएम करेंगे लोकार्पण

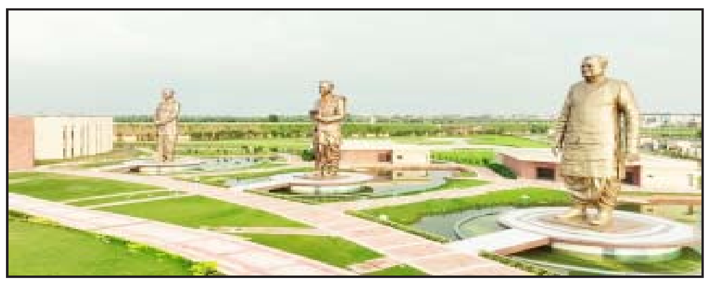

लखनऊ, (संवाददाता)। पुराने शहर में पड़ने वाली एलडीए की बसंतकुंज योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है। इस समय फिनिशिंग का काम चल रहा है। यह स्थल ऊपर से देखने पर कमल की आकृति में नजर आता है। यहां पर भारत माता की सुदर्शन चक्र लिए हुए प्रतिमा, कमल के फूल और दीये की आकृति के बड़े मॉडल भी स्थापित किए जाएंगे। इसका लोकार्पण 25 दिसंबर को भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। इसके बाद पुराने शहर को एक बड़ा आयोजन स्थल और मनोरंजन के लिए नया पार्क मिल जाएगा। प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पं. दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं हैं। तीनों प्रतिमाएं कांस्य की हैं, जो 65 फीट ऊंची हैं। इनके निर्माण पर 21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये प्रतिमाएं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रमुख मूर्तिकार रामसुतार और माटूराम ने बनाई हैं। तीनों विभूतियों से जुड़ी यादों को संजोने के लिए म्यूजियम भी बना है। इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्रेरणा स्थल पर म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, तीन हैलीपैड, रैली आदि के लिए काफी बड़ा मंच विकसित किया गया है। म्यूजियम ब्लॉक में दीये की आकृति वाला मॉडल लगाए जाने के बारे में जानकारों का कहना है कि पहले यही आकृति जनसंघ की पहचान थी। प्रेरणा स्थल में सिविल से जुड़े सभी कार्य पूरे हो गए हैं। म्यूजियम ब्लॉक को सजाने का काम चल रहा है। यहीं तीनों महान विभूतियों के जीवन से जुड़ी जानकारियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को दर्शाया जा रहा है। म्यूजियम ब्लॉक लगभग 6300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बना है। इसमें वीवीआईपी व जन सामान्य के लिए दो अलग गेट हैं। पांच गैलरी हैं, जिनमें तीनों विभूतियों की तस्वीरें, स्टोन म्यूरल्स के साथ ही डिजिटल पैनल पर लाइव ऑडियो–वीडियो विजुअल्स प्रदर्शित किए जाएंगे।

एलडीए के मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा का कहना है कि प्रेरणा स्थल का काम पूरा हो गया है। म्यूजियम में इस समय फिनिशिंग का काम चल रहा है। यह भी 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों के इसका लोकार्पण प्रस्तावित है।

खत्म नहीं हुआ इंडिगो संकट, 15 उड़ाने फिर हुईं रद्द

लखनऊ, (संवाददाता)। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले पांच दिनों से गड़बड़ाया विमानों का संचालन अब भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आया है। मंगलवार को आने और यहां से जाने वाली 15 फ्लाइटें निरस्त हुईं और आठ देरी से उड़ीं। इसके चलते करीब 5,400 यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उड़ान निरस्त होने और देरी के चलते 190 यात्रियों ने अपने टिकट भी निरस्त कराए। हालांकि, यात्रियों को कुछ राहत रही, क्योंकि कई फ्लाइटें समय पर गईं। इंडिगो के काउंटर पर अफरातफरी भी कम रही। मंगलवार को जो फ्लाइटें निरस्त रही हैं, उनमें दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद की फ्लाइटें शामिल हैं। इन फ्लाइटों के निरस्त होने की जानकारी यात्रियों को समय पर नहीं मिल सकी। ऐसे में यात्री इधर–उधर काउंटर पर भटकते रहे। सीतापुर से आए अतुल सिंह ने बताया कि उन्हें रात 10रू45 बजे बेंगलूरू जाने वाली इंडिगो की उड़ान से जाना था, मगर यहां पहुंचने पर बताया गया कि फ्लाइट निरस्त कर दी गई है। अब इंडिगो वाले कह रहे हैं कि बुधवार को फ्लाइट मिलेगी। इसी तरह अयोध्या निवासी विवेक ने बताया कि शाम 7रू20 बजे दिल्ली जाने वाली उनकी इंडिगो की उड़ान निरस्त हो गई। अब इंडिगो कर्मचारी कह रहे हैं कि बुधवार को भेज देंगे। मोहम्मद नदीम ने भी बताया कि उन्हें मुंबई और वहां से बहरीन जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पता चला कि शाम 7रू40 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट निरस्त हो गई है। अब उन्हें बुधवार को भेजेंगे। ऐसे में रात भर लखनऊ में रुकना पड़ेगा।

संक्षिप्त खबरें

अमीनाबाद घंटाघर पार्क के पास नई पार्किंग शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अमीनाबाद के घंटाघर पार्क में मंगलवार को खुली पार्किंग शुरू हो गई। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने पार्किंग का लोकार्पण किया। महापौर सुषमा खर्कवाल भी इस मौके पर मौजूद रहीं। यहां 200 दो पहिया और 35 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। अमीनाबाद बाजार में पार्किंग की कमी का मुद्दा अमर उजाला ने बीते दिनों प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नगर निगम प्रशासन जागा। प्रभारी मंत्री ने भी मौके का दौरा कर

घंटाघर पार्क की खाली जमीन पर खुली पार्किंग बनाने के लिए कहा था। इसके लिए अवस्थापना निधि में बजट पास किया गया, जिसके बाद अब यह चालू हो गया है। नगर निगम जोन–एक के अधिकारी और निगम के पार्किंग प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि इस पार्किंग में 235 वाहनों की क्षमता है। यहां 200 दोपहिया वाहन और 35 चार पहिया वाहन आसानी से खड़े हो सकते हैं। इस पार्किंग के शुरू होने से अमीनाबाद बाजार में वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था और जाम की समस्या कम होगी। लोगों को वाहनों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रीय पार्षद ने भी पार्किंग शुरू होने पर खुशी जताई। पार्किंग प्रभारी ने बताया कि शहर में करीब 70 खुली पार्किंग शुरू करने की तैयारी है। इनमें अमीनाबाद की दो और पार्किंग शामिल हैं। एक रामाबुक डिपो के सामने और एक झंडे वाला पार्क में बने शेल्टर होम के पास की है। इनके शुरू होने के बाद जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी।

सामाजिक परिवर्तन के साहित्य पर हुई चर्चा

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषाएं (एमईएल) विभाग की ओर से मंगलवार को सामाजिक परिवर्तन, साहित्य और शासन विषय को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। इसका शुभारंभ ओएनजीसी भवन में प्रो. मैत्रेयी प्रियदर्शिनी ने किया। कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने साहित्य–मनोविज्ञान के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि प्रो. अरविंद मोहन, वक्ता प्रो. राजेश मिश्रा और प्रो. विकास शर्मा व प्रो. आर. पी. सिंह ने साहित्य की सामाजिक भूमिका और शासन से उसके संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कार्यक्रम में 150 से अधिक शोधार्थियों ने हिस्सा लिया।

नौ लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है प्रदेश का बजट

लखनऊ, (संवाददाता)। वित्त विभाग ने उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के तहत मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति 2025 जारी की है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रदेश के कुल बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त विभाग के अनुमानों के मुताबिक इसके बाद वित्तीय वर्ष 2027–28 में बजट का आकार 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2028–29 में बजट 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इस तरह आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश के बजट में हर साल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2029–30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दस खरब रुपये तक पहुंचाना है। इसे देखते हुए आने वाले वर्षों में बजट का आकार मौजूदा अनुमानों से भी अधिक हो सकता है। सरकार का फोकस निवेश बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में तेज विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए अलग–अलग स्तरों पर विभागीय तैयारियां चल रही हैं। प्रस्तावित विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार सरकार तय करेगी। हालांकि, विभागों ने मौजूदा योजनाओं को पूरा करने और अतिरिक्त बजट की मांग से जुड़े प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना शुरू कर दिए हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट 808736.06 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधायी कार्य संपन्न कराएगी।

प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी ऑनलाइन हाजिरी, स्कूल शुरू होने के एक घंटे के अंदर देनी होगी अटेंडेंस

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी अब ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिक्षकों को विद्यालय शुरू होने के एक घंटे के अंदर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे। प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में तैनात 4.50 शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विद्यालय शुरू होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। नेटवर्क की दिक्कत से हाजिरी दर्ज करने में समस्या पर ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह नेटवर्क सुचारु होने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा इसमें असमर्थता व्यक्त करने पर यह जिम्मेदारी दूसरे शिक्षक को दी जाएगी। अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा बिना शिक्षक का पक्ष जाने शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी निर्देश में कहा है कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इससे शासन को अवगत कराएं। 2024 में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया गया था।

संक्षिप्त खबरें

वाराणसी में बिजली बिल राहत योजना शिविर का निरीक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने वाराणसी प्रवास के दौरान रोहनिया स्थित विद्युत उपकेंद्र पर आयोजित बिजली बिल राहत योजना शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में भारी संख्या में उपभोक्ताओं की उपस्थिति रही, जो यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार की यह ऐतिहासिक योजना जनता के बीच तेजी से विश्वास और लोकप्रियता बना रही है। आज के शिविर में कुल 173 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो उपभोक्ता हित में चल रही इस योजना की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है।निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने उपस्थित उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन पर वर्षों से बिजली बिल का भारी बोझ था। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के अपने बकाया का निपटारा कर सकें और आगे नियमित एवं सरल बिलिंग व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकें।ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का समाधान करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाया है, ताकि हर पात्र उपभोक्ता तक यह सुविधा आसानी से पहुंचे।

आयुष विभाग की समीक्षा बैठक मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने गुणवत्ता

लखनऊ (आरएनएस)प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एमओएस) डॉ. दयाशंकर मिश्र ''दयालु'' ने आज विधानसभा कार्यालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयुष विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापरक और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।मंत्री ने कहा कि जो निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, उनके लोकार्पण की प्रक्रिया प्राथमिकता पर पूरी की जाए। वहीं, जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, उनके बारे में तुरंत जानकारी दी जाए ताकि उसका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।डॉ. दयालु ने अधिकारियों को आयुष चिकित्सालयों में औषधियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आयुष चिकित्सालयों में औषधियों की कोई कमी न हो और सामान्य जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।साथ ही, मंत्री ने आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी निदेशालयों में प्रोन्नति और सेवा संबंधी मामलों की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने लम्बित रिक्तियों के सापेक्ष संबंधित आयोग को अधियाचन भेजने और कर्मचारियों के निलम्बन, जांच एवं एसीपी जैसे मामलों की प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार ने मंत्री डॉ. दयालु को विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया और आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन किया जाएगा।बैठक में आयुष महानिदेशक सुश्री चौत्रा बी., निदेशक होम्योपैथ डॉ. पी.के. सिंह, यूनानी निदेशक प्रोफेसर जमाल अख्तर तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

गोवंश के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश के भरण–पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये की राशि भरण–पोषण के लिए निर्धारित की गई है, जिसका कोई भी दुरुपयोग या फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी गोवंश भूखा न रहे और पशुचिकित्साधिकारी इसके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करें।उन्होंने गोशालाओं में ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने और किसी भी गोवंश की ठंड से मृत्यु न होने पर भी जोर दिया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गोसंरक्षण और गोआधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गौ–दुग्ध, गोबर और गोमूत्र के व्यवसायिक उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संचालित योजनाओं की रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाए और लघु पशु योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। गोआश्रय स्थल के प्रभारी, पशुचिकित्साधिकारी और अन्य अधिकारी औषधियों, भूसा, चारे की मात्रा और गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें।मंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुग्ध उत्पादकों का मूल्य भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए और उनके पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल सुधार के लिए पीसीडीएफ की पशुआहार निर्माणशालाओं में निर्मित पशुआहार, मिनरल मिक्चर और आवश्यक दवाओं का वितरण निर्धारित समय में किया जाए।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 7664 दुग्ध समितियां सक्रिय हैं। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत 2250 समिति गठन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और पंजीकृत पोर्टल पर 2470 समितियां निबंधित हैं।पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने मंत्री धर्मपाल सिंह को आश्वस्त किया कि दिए गए ।

कौशांबी के कड़ा धाम में पर्यटन को नई पहचान

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कौशांबी जिले के सिराथू तहसील स्थित कड़ा धाम के कुबरी घाट को नई पहचान देते हुए आरती स्थल के विकास कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। करीब 2.41 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार यह विकास कार्य इक्यावन शक्तिपीठों में से एक मां शीतला धाम की महिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।उन्होंने बताया कि कौशांबी प्रदेश के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर एक चमकता हुआ केंद्र बनकर उभर रहा है। भगवान बुद्ध की पावन भूमि होने के साथ–साथ यह क्षेत्र हिन्दू धर्मावलंबियों के लिए भी गहरी आस्था का स्थान है। कुबरी घाट का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व लंबे समय से रहा है, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान और पूजा–अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इसी वजह से आरती स्थल के विकास को प्राथमिकता दी गई, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वे सुरक्षित वातावरण में दर्शन–पूजन कर सकें। शीतला धाम कड़ापीठ शक्ति उपासकों का प्राचीन केंद्र है। स्कंद पुराण के अनुसार, जहां–जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। माना जाता है कि कराकोटम जंगल में देवी सती का दाहिना कर जिस स्थान पर गिरा, वही आज कड़ा धाम के रूप में विख्यात है। यह स्थल न सिर्फ धार्मिक मान्यता का केंद्र है, बल्कि देश–दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का आधार भी है।

अंतर्देशीय जल परिवहन उत्तर प्रदेश के लिए नए अवसर के रूप में उभर रहा है

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन एक नए अवसर के रूप में उभर रहा है। देश में चिन्हित 111 वाटर इनलैंड प्रोजेक्ट्स में से 11 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश में जल का अपार भंडार है और प्राचीन काल से ही लोग जलमार्गों का उपयोग आवागमन और व्यापार के लिए करते आए हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने यह बातें उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की लखनऊ में आयोजित प्रथम बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश प्राचीन शहर नदियों के किनारे बसे हैं और इसका मुख्य कारण जलमार्गों का अस्तित्व और उसका इस्तेमाल था। मंत्री ने ऐतिहासिक दृष्टांत देते हुए बताया कि भारत की राजकुमारी सुरीरत्ना अयोध्या से कोरिया तक जलमार्ग के माध्यम से गई थीं और उस यात्रा में प्रयुक्त जहाज आज भी स्थानीय म्यूजियम में संरक्षित है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नदियों के अलावा और भी जल स्रोत हैं, जैसे बलिया का सूराहाताल और गोरखपुर का रामगढ़ ताल, जो पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जल परिवहन पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने का एक कारगर माध्यम हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होता है।दयाशंकर सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि जल मार्गों पर फ्लोटिंग होटल और रेस्टोरेंट के माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने उपस्थित विचारकों और अधिकारियों से आग्रह किया कि यदि व्यक्तिगत रुचि और निवेश के साथ जल परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए तो यह प्रदेश के परिवहन और पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित कर सकता है।

लखनऊ में "उत्तर प्रदेश सीएसआर राउंडटेबल 2025 ऑन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी" का सफल आयोजन : कौशल और रोजगार पर उद्योग–सरकारी साझेदारी को नई दिशा

लखनऊ, (संवाददाता)। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में ''उत्तर प्रदेश सीएसआर राउंडटेबल 2025 ऑन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी'' का सफल आयोजन किया गया। इस परामर्श–सत्र में देश की 30 से अधिक प्रमुख कंपनियों, फाउंडेशनों एवं संस्थानों ने भाग लेकर प्रदेश के कौशल एवं रोजगार पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा की। यह आयोजन योगी सरकार के नेतृत्व में राज्य को एक भविष्य–उन्मुख, सक्षम और कौशल–प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की निरंतर पहलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के मार्गदर्शन में विभाग व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, उभरते कौशल क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार करने और उद्योग–संलग्न प्रशिक्षण मॉडल को बढ़ावा देने में सक्रिय है। योगी सरकार के विजन के अनुरूप युवाओं को उद्योग–उन्मुख कौशल से जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग डॉ. हरि ओम ने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल–आधारित मानव संसाधन निर्माण के लिए व्यापक संरचनात्मक सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रशिक्षण अवसंरचना को जिला एवं ब्लॉक स्तर तक सुदृढ़ किया जा रहा है, स्मार्ट लैब्स और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उद्योग–संलग्न पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ बढ़ती साझेदारी से रोजगारपरक कौशल विकास को नई गति मिल रही है और युवाओं के लिए उन्नत अवसर खुल रहे हैं।मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पुलकित खरे ने बताया कि सीएसआर आधारित सहयोग के माध्यम से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और अधिक प्रभावी होगा। यूपीएसडीएम द्वारा डिजिटल कौशल, हरित कौशल, उन्नत विनिर्माण तकनीक, सेवा–क्षेत्र आधारित रोजगार तथा महिला–प्रधान आजीविका कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी अपरेंटिसशिप को मजबूत करेगी और प्रदेश का युवा वर्ग सीधे उद्योग से जुड़कर रोजगार सृजन में सक्षम होगा।अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी यह प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख ''राष्ट्रीय प्रतिभा केंद्र'' के रूप में उभर रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व में सरकारी, औद्योगिक और सीएसआर साझेदारियों का यह सशक्त ढांचा आने वाले वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार अवसरों का विस्तार करेगा और राज्य के आर्थिक परिवर्तन को नई गति प्रदान करेगा।राउंडटेबल में एचसीएल, एक्सिस बैंक, ह्युंडई, सीमेंस, टाटा ट्रस्ट्स, रिलायंस फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन सहित अनेक अग्रणी संगठनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने जिला–स्तरीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर हस्तक्षेपों के संरेखण, पाठ्यचर्या में उद्योग की मांग के अनुसार सुधार और प्रशिक्षण के परिणामों को मजबूत करने संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए। सीएसआरबॉक्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भौमिक शाह ने कहा कि यह राउंडटेबल उत्तर प्रदेश में कौशल एवं रोजगार सृजन के लिए उद्देश्य–प्रधान साझेदारियों को नई दिशा देगा और राज्य की विजन 2047 की यात्रा में इसकी भूमिका और सुदृढ़ होगी।कार्यक्रम के अंत में आईबीएम, लेनोवो, सीमेंस तथा बजाज (टाटा स्ट्राइव के माध्यम से) ने लक्षित कौशल विकास पहलों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए। जेनरेशन इंडिया फाउंडेशन ने रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से युवाओं को उद्योग–संगत कौशल प्रदान करने के नए अवसर खुलेंगे।

अयोध्या मे बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर मे तीन श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या ।गुरुवार को भोर लगभग 5 बजे प्रयागराज हाईवे पर थाना पूराकलंदर क्षेत्र के कल्याण भदरसा गांव के पास उस समय दिल दहला देने वाला हादसा हो गया ।जब अयोध्या दर्शन के लिए आ रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो सामने से आ रही ट्रैक्टर–ट्राली से टकरा गई ।टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए ।हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे ।सूचना मिलते ही सीओ अयोध्या आशुतोष, थाना अध्यक्ष पूराकलंदर

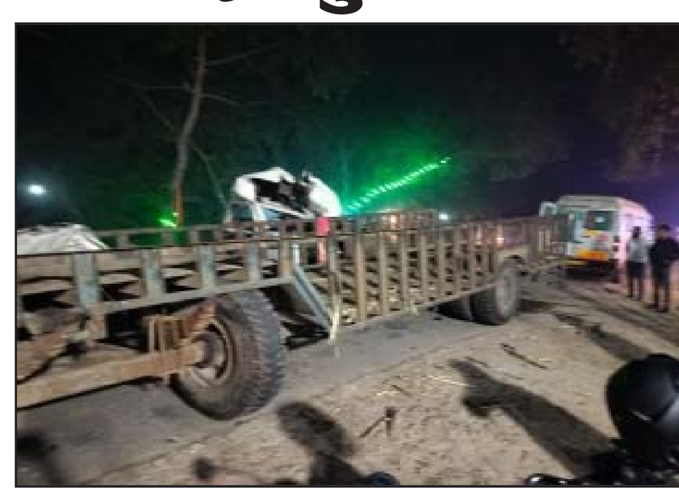

मनोज शर्मा व अन्य पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया ।कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है ।हादसे के बाद हाईवे पर लंबी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि इस हादसे में अंकिता पटेल 25 वर्ष,मीरा बाई 25 वर्ष व राम यश मिश्रा 50 वर्ष सभी निवासी बेलहाई थाना मऊगंज रीवां मध्य प्रदेश के है ।जिनकी मौत हो गई ।वही घायलों मे कुसुमवती पटेल पत्नी सरोजमनी पटेल उम्र 35 वर्ष,चंद्रकली पटेल पत्नी चित्रसेन उम्र 45,शिवांश पटेल पुत्र हरिकेश उम्र 5 वर्ष,शशि पटेल पत्नी हरिकेश पटेल उम्र 30 वर्ष,दीपक पटेल पुत्र चित्रसेन पटेल उम्र 35,चित्रसेन पटेल पुत्र इंद्रभान उम्र 50 व आशीष पटेल पुत्र सरोजमनी पटेल उम्र 23 वर्ष शामिल है। बताया कि गंभीर रूप से घायलों में तीन को मंडलीय चिकित्सालय तथा शेष चार घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या की देखरेख में 13 दिसंबर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा ।राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है ।राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नांकित विषयों से संबन्धित वादों का निस्तारण किया जायेगा ।प्रिलिटीगेशन स्तर के विवाद धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर) व अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद)न्यायालय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो)– आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐ, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हों व अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि। उक्त जानकारी अनिल कुमार वर्मा अपर जनपद न्यायाधीशध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या ने दी है।

संक्षिप्त खबरें

चाइनीज मंझे की चपेट में आने से प्राइवेट शिक्षक की मौत,परिजनों में मचा कोहराम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,11 दिसंबर। यूपी के जौनपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर गुरुवार की सुबह लगभग 8रू00 बजे संदीप तिवारी (40) साल पुत्र विष्णु दत्त तिवारी निवासी उमरपुर हरिबंधनपुर अपनी बेटी मन्नत को जो की कक्षा 2 की छात्रा है बाइक से सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर घर जारहे थे कि जैसे ही वह शास्त्री ब्रिज पर पहुंचे चाइनीज मंझे की चपेट में आ गए जहां पर उनकी गर्दन बुरी तरह से कट गई स्थानीय लोगों के सहयोग से एंबुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है चाइनीज मांझा बंद होने के बाद भी आज भी खुलेआम धड़ले से बिक रहा है जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है ।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही इस मामले में कोतवाली प्रभारी विश्व नाथ प्रताप सिंह ने बताया कि लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। देर शाम शव पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर अपने पैतृक आवास अम्बेडकर नगर रवाना हो गए। घटना के समय पत्नी अपने मायके गई थी।

नगर निगम ने यात्रियों व जनता के लिए ठंड से बचाने के लिए खोला 60 बेड का रैनबसेरा

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। रामनगरी आने वाले जन सामान्य को ठंड के दौरान आवासीय व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए नगर निगम ने अस्थाई रैन बसेरे की स्थापना की कवायद तेज कर दी है। अयोध्या कैंट क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड एवं गांधी पार्क में 30–30 बेड के अस्थाई रैन बसेरा स्थापित किए गए हैं ।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि शीत लहरी और तापमान में निरंतर गिरावट को देखते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर निगम को लोगों को ठंड से बचने के लिए त्वरित उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय क्षेत्र में आठ अस्थाई एवं स्थाई रैन बसेरा स्थापित किया जाना है। अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड एवं गांधी पार्क में 30–30 बेड का रैन बसेरा बनाया गया हैं, जिसमें दोनों जगह 15–15 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन एवं साकेत अंडरपास पर भी जल्द ही रंग बसेरा चालू कर दिया जाएगा।

'पुलिस पर हमले के दो मुख्य आरोपी अब भी फरार,22 दिन बाद भी गिरफ्तारी दूर'

ब्यूरो चीफ – आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। हलियापुर थाना क्षेत्र के डोभियारा लाला का पुरवा गांव में 20 नवंबर को दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले को 22 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस पर जानलेवा हमला कर सरकारी असलहा और कारतूस लूट ले जाने वाले मुख्य आरोपी आदर्श सिंह और उसके पिता दशरथ सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में लगातार बेचौनी बनी हुई है ।घटना के दिन अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र से पहुंचे दो दारोगा और एक सिपाही पर आरोपियों ने हमला बोल दिया था। हाथापाई के दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर, मैग्जीन, दस कारतूस और मोबाइल फोन लूट लिए गए थे। मामले के खुलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं।हलियापुर पुलिस ने तीन दिन बाद शिवम सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ अखिल, प्रमिला सिंह और शिवानी सिंह को गिरफ्तार कर लूटी गई सरकारी पिस्टल व कारतूस बरामद तो कर लिए, लेकिन घटना के दो मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और लगातार पुलिस को चकमा दे रहे हैं।इस बीच नवागत थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरि के सामने यह केस उनकी कार्यशैली की पहली बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। संभावित ठिकानों पर दबिशें जारी हैं,लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है ।स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि पुलिस पर हमले जैसे गंभीर मामले में आरोपी इतने दिनों तक फरारी कैसे काट रहे हैं।

त्वचा के मरीज को देख रहे बच्चों के डॉक्टर, हार्ट और ईएनटी रामभरोसे

भदोही, (संवाददाता)। जिले में स्किन की समस्या के मरीजों को बच्चों के डॉक्टर, हार्ट और ईएनटी जैसी बीमारियों में फिजीशियन या सामान्य चिकित्सक ही देख रहे हैं। चिकित्सकों की कमी के बीच मरीजों को अस्पतालों में तैनात प्लेन एमबीबीएस चिकित्सकों से उपचार कराना पड़ता है। जिले में एक भी कॉडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। स्किन व ईएनटी के एक–एक चिकित्सक हैं। सीएचसी पर त्वचा, ईएनटी सहित विभिन्न विशेषज्ञों की कमी है। जिले में रेगुलर और संविदा के कुल 135 डॉक्टरों की तैनाती 29 स्वास्थ्य केंद्रों पर की गई है। जिले की आबादी करीब 20 लाख है। 1994 में अस्तित्व में आए। भदोही जिले में अब तक चिकित्सकीय व्यवस्था में कई सुधार हुए हैं ।

हरिद्वार स्थित एसबीएल कंपनी में अयोध्या होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण सफल

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। देवकाली स्थित राजकीय डॉ. ब्रिज किशोर होम्योपैथिक

मेडिकल कॉलेज, अयोध्या के छात्र–छात्राओं का हरिद्वार स्थित देश की प्रमुख होम्योपैथिक औषधि निर्माण इकाई एसबीएल कंपनी में आयोजित शैक्षणिक भ्रमण बेहद सफल और ज्ञानवर्धक रहा ।विद्यार्थियों ने आधुनिक औषधि निर्माण, अनुसंधान प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया ।इस शैक्षणिक यात्रा का नेतृत्व कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार सिंह ने किया। साथ ही प्रोफेसर डॉ. चंद्रशेखर यादव (विभागाध्यक्ष, होम्योपैथिक फार्मेसी), डॉ. सुधीर चौहान और डॉ. अंजू रागिनी छात्रों के साथ मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहे। शिक्षकों ने भ्रमण के दौरान तकनीकी बिंदुओं को सरल भाषा में समझाते हुए छात्रों का मार्गदर्शन किया ।कंपनी के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रमुख इकाइयों,उत्पादन विभाग पैकेजिंग सेक्शन,क्वालिटी कंट्रोल लैब,रिसर्च एंड डेवलपमेंट (त्–क) का विस्तृत अवलोकन कराया। विद्यार्थियों ने जर्मन तकनीक आधारित आधुनिक मशीनरी और ळडच मानकों से संचालित उत्पादन प्रक्रियाओं को करीब से देखा ।विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कच्चे माल के चयन से लेकर दवाओं की अंतिम पैकेजिंग तक की वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। छात्रों ने डवजीमत ज्पदबजनतम निर्माण, ज्तपजनतंजपवदे, क्पसनजपवदे और च्वजमदजप्रंजपवद जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी चरणों को प्रत्यक्ष रूप में समझा ।विभागाध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर यादव ने कहा कि इस प्रकार के औद्योगिक भ्रमण विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। डॉ. सुधीर चौहान ने इसे छात्रों के करियर विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया ।वहीं डॉ. अंजू रागिनी ने कहा कि विद्यार्थियों को उद्योग की आधुनिक आवश्यकता और वैज्ञानिक सोच समझने का सुनहरा अवसर मिला।

डॉ अरुण कुमार भरारी को मिली प्रोफेसर की उपाधि

राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन– भारत , आराध्य राम जी ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी तथा द ग्लोबल ट्रेनिंग एंड रिसर्च मल्टीवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विगत दो दशकों से भी अधिक समय से नेचुरोपैथी,योग, हेल्थ केयर, प्राथमिक उपचार, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर एंड वैलनेस के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाइजेशन (आई0एन0ओ0) के उत्तर प्रदेश के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉ० अरुण कुमार भरारी को द ग्लोबल ट्रेनिंग एंड रिसर्च मल्टीवर्सिटी द्वारा प्रोफेसर का टाइटल प्रदान किया गया। डॉ० भरारी को पूर्व में भी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, परंपरागत प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग भास्कर की मानद उपाधि, पूर्ण–प्रग्णा अवार्ड तथा भारत–गौरव अवार्ड जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ०आर०के० स्वर्णकार(ए०डी०जी०,पी०ए०सी०) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विशेष सचिव ड०सी०पी० शर्मा,राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन–भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ०रामजी शर्मा, डॉ० ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव,हिंदू महासभा से चंद्रशेखर सिंह, चारु श्रीवास्तव, रविकांत विश्वकर्मा, रविप्रताप नारायण, प्रियंका तिवारी, सुनील कुमार द्विवेदी, योग प्रशिक्षक महेश कुमार, डॉ० विनोद कुमार यादव, डॉ० राकेश प्रताप सिंह, डॉ० शोभा रानी, डॉ० दीपक शर्मा, डॉ० एस० के० पाल, डॉ० विवेक शर्मा, डॉ० कल्पना सिंह, लक्ष्मी मिश्रा, रजनी मिश्रा, सोनी शुक्ला, डॉ० टी० आर० सिंह (अधिवक्ता), विपिन शर्मा, एडवोकेट विनय कुमार शर्मा, श्री हुंकार दास जी महाराज, ज्योति सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे!

संक्षिप्त खबरें

परेशान किसानों को 16 गोवंशों को होलिका स्थल में किया बंद

सीतापुर, (संवाददाता)। निराश्रित गोवंशों से परेशान किसानों ने मंगलवार को 16 गोवंशों को होलिका स्थल पर बंद कर दिया। इसके बाद किसान इन गोवंशों को एक ट्रॉली में भरकर गोशाला छोड़ आए। मोहल्ला अंबर सरांय में गोवंशों से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में भारी संख्या में गोवंश बाहर से लाकर यहां छोड़ दिए गए हैं। ये गोवंश फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे नाराज किसानों ने गोवंशों को पकड़कर मोहल्ले में बने होलिका स्थल में बंद कर दिया। किसानों ने बताया कि पकड़ में आए गोवंश उनकी फसलों को चट कर रहे थे। किसानों ने बताया कि ग्राम अनियाकला के पूसूपुरवा गोशाला संचालक से बात की गई है। इन गोवंशों को ट्रॉली में भरकर गोशाला में छोड़ दिया गया।

गवाही देने वाले युवक के घर के बाहर की फायरिंग

सीतापुर, (संवाददाता)। रोहिला गांव में सोमवार रात दबंगों ने गवाही देने वाले युवक के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी। पीड़ित ने वीडियो आदि साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी। शिकायत के बाद चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रोहिला निवासी अवधेश अवस्थी के अनुसार रात तकरीबन दो बजे गांव के सौरभ त्रिवेदी, प्रशांत वाजपेयी, शिव किशोर, महोली के भट्ठा निवासी रजनीश मिश्र उनके घर पर आ धमके। आरोपियों ने पहले गालियां दी, इसके बाद फायरिंग कर दहशत फैला दी। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर इकठ्ठा होने लगे तो आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित अवधेश ने बताया कि वर्ष 2021 में नाली के विवाद में गांव निवासी त्रिवेदी परिवार से उनके परिवार का झगड़ा हुआ था। इसमें उनके पारिवारिक सदस्य विनोद अवस्थी की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में चार लोग जेल में बंद हैं। कोर्ट में चल रहे मुकदमे में उनकी गवाही होनी है। इसलिए आरोपी के परिवार के लोग चाहते हैं कि गवाही न हो पाए। पीड़ित ने मौके पर वीडियो आदि बनाकर पुलिस को सौंप दिया है। इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश जारी है।

कॉम्बिंग में नहीं मिले तेंदुए के पगचिह्न

सीतापुर, (संवाददाता)। वन विभाग की टीम ने मंगलवार को मुसब्बरपुर गांव के आसपास कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चला। कहीं पर ताजा पगचिह्न भी नहीं मिले हैं। हालांकि इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समूह में खेतों की तरफ जाने के लिए जागरूक किया। मंगलवार शाम मुसब्बरपुर जंगल के निकट लगाए गए पिंजरे में शिकार के लिए बकरी बांधी गई। रेंजर कल्पेश्वर नाथ भार्गव ने बताया कि मंगलवार को कहीं भी ताजा पगचिह्न नहीं मिले हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया है।

सीएम योगी ने राज्यमंत्री गिरीशचन्द्र के घर पहुंच कर दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,11 दिसंबर । यूपी के जौनपुर में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 1रू30 बजे राज्यमंत्री गिरीशचंद यादव के घर पहुंचे । समसपुर पनियरिया में पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय सवधु यादव के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दिया। इसके बाद वह सीधे घर के अंदर उनकी माता समेत परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढस बधाते सत्वना दी। और सहयोग का भरोसा दिया। करीब 10 मिनट तक परिजनो से मुलाकात के बाद वह घर के बाहर निकले, उन्होंने पुलिस रस्सी घेरा के अंदर होकर वहां मौजूद भीड़ व कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान भीड़ से आवाज आई जय श्री राम राधे राधे, भीड़ की हलचल पर पुलिस प्रशासन सकते में आ गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी बात पर ध्यान न देते हुए वह सीधे फॉर्च्यूनर कर कार में बैठकर हेलीपैड स्थल की ओर रवाना हो गये। जहां करीब 1रू45 पर वह हेलिकॉप्टर से वाराणसी के लिए रवाना हो गया। इसके पूर्व हेलीपैड स्थल पर भाजपा के नेताओं जनप्रतिनिधियों विधायकों से मुलाकात की। वहां डीआईजी वैभव कृष्ण, जिला अधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ से जिले के हालात के बारे में जानकारी ली। पुलिस व्यवस्था चाक चौबन्द थी, जिससे कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होने पाई। गिरीशचन्द्र यादव से व्यक्तिगत बात करके उन्होंने सांत्वना देते हुए दुख जताया। इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण कैबिनेट मंत्री डॉ स्वतंत्रदेव सिंह उनके साथ हेलीकॉप्टर से वाराणसी के लिए रवाना हो गए।

सुरक्षा व्यवस्था चक्रवर्ती रही खेतों छतो से पुलिस की पैनी नजर

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां सभी प्रशासनिक विभाग हाईअलर्ट पर रहे। वह वही एक किलोमीटर के अंदर आने जाने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। खेत खलियानों से लेकर छतो व पेड़ों पर पुलिस मुस्तैद रही वहां से पैनी नजर लोगों पर रख रही थी ।इसके साथ ही सड़क या किसी भी मार्ग से आने जाने वालों की सघन जांच भी की जा रही थी, लोगों की छानबीन कर ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा था ।उधर हेलीकॉप्टर स्थल पर उतरते ही दूर से देखने वाले लोग चिल्लाने लगे, लेकिन सुरक्षा के बीच हेलीपैड स्थल तक कोई नहीं पहुंच सका दूर से ही शोर करते रहे । सादे ड्रेस में महिला व पुरुष पुलिस घर से लेकर बाहर तक भीड़ में भी तैनात थे। राज्यमंत्री के घर से करीब 500 दूर सभी पार्किंग की व्यवस्था की गई थी । वहां से लोग उनके घर तक पैदल ही पहुंच रहे थे और उनके घर कि किसी भी नेता से नहीं मिले न ही बातचीत नहीं किया । वहां मौजूद सभी का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और चलते बने।

हेलीपैड पर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे उन्होंने उनके पिता के चित्र पर श्रद्धांजलि दी और परिजनो से मुलाकात की कर संत्वना दी इसके बाद वह हेलीपैड स्थल पर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिसीव किया।

इस मौके पर हेलीपैड स्थल पर

पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह , पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह

पूर्व जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह

जिला मंत्री पीयूष गुप्ता , नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य,

रागिनी सिंह महिला मोर्चा अध्यक्ष,

जिला मंत्री राजू सिंह दादा, सदस्य महिला कल्याण बोर्ड गीता विन्द,

संदीप तिवारी , पूर्व जिला उपाध्यक्ष

पंकज मिश्रा, सूर्यप्रकाश सिंह प्रबंधक मुन्ना, पूर्व विधायक बाकेलाल सोनकर , पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव,आशीष गुप्ता , श्याम मोहन अग्रवाल ,भाजपा नेता

अजय सिंह खरचू , राजकेशर पाल चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति ,प्रशांत सिंह दीपक ,कमलेश निषाद , उपेंद्र नाथ मिश्रा , ध्धर्मेंद्र मिश्रा , राजदेव यादव ,रामसूरत मौर्या ,रमेश यादव मौजूद रहे।

सफारी वाहनों से बाघ को घेरने के मामले में कमिश्नर सख्त

पीलीभीत, (संवाददाता)। पर्यटन के नाम पर वन्यजीवों की सुरक्षा से खिलवाड़ अब अधिकारियों के गले की हड्डी बन गया है। बराही रेंज में सायफन पुल पर बाघ का रास्ता रोककर सफारी वाहन खड़े करने की लापरवाही का वीडियो वायरल होने के बाद उच्च स्तर तक हलचल मच गई है। बरेली मंडल के कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने घटना को गंभीर मानते हुए डीएम को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पूरे वन विभाग और पर्यटन स्टाफ में खलबली मची है। डीएम के निर्देश पर एआरटीओ ने जांच शुरू कर दी है। पीटीआर के पर्यटन सत्र के दौरान सैलानियों की सुविधा के साथ नियमों का पालन कराने के निर्देश जारी किए जाते हैं। खासकर सफारी के दौरान बाघ दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी और रास्ता को न रोकने पर विशेष जोर दिया जाता है लेकिन रविवार को सफारी के दौरान नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया था। जबकि सफारी के दौरान कुछ जिप्सी वाहनों को सायफन पुल की ओर ले जाया गया और पुल पर विचरण कर रहे बाघ के रास्ते को दोनों ओर वाहन लगाकर रोका गया था। सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद अफसर गंभीर हुए थे। मामले में चार वाहनों के चालक, गाइड के अलावा रेंजर, बीट प्रभारी, वाचर को नोटिस जारी किया था। इधर मामले का कमिश्नर एस चौधरी ने संज्ञान लिया। मंगलवार को उन्होंने डीएम से पूरे मामले की जानकारी जुटाई और मामले को गंभीर बताकर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की जांच तेज करते हुए एआरटीओ को संबंधित वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। एआरटीओ ने डीएफओ से सभी वाहनों के नंबर और डिटेल मांग ली है। – मामले में वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को डीएफओ मनीष सिंह ने रेंजर समेत 11 लोगों को नोटिस जारी किया था। इधर मामला तूल पकड़ने के बाद पर्यटन प्रभारी सुरेंद्र गौतम को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। माना जा रहा है कि प्रकरण से संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पूरे मामले की जांच एसडीओ माला रुद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।